श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने अभी प्रश्न के उत्तर में बताया है कि गांधी सागर बांध का सर्वेक्षण कराने की योजना सरकार की है और इसका तात्पर्य यह हैं कि इसको देश का अच्छे से अच्छा बांध बनाया जाये तो इसमें पानी का अधिक स्टोर किया जा सके, अधिक से अधिक सिंचाई की जा सके और आस पास के जो प्रान्त है जो बिजली लेते हैं उनको अधिक बिजली मिल सके, अधिक पानी मिल सके, इसके लिये क्या सरकार के पास कोई निश्चित योजना है ?

DR. K. L. RAO : A number of dams have been constructed on the Chambal river, and every drop of water that falls in this area is being utilised. There is no other river in that area which is one of the scarcity areas. There is no other river in the vicinity and Chambal is the only river in that area. The Chambal itself has been planned completely and three dams have been constructed and have been nearly completed, and there is a barrage and and so on. There is nothing more that can be done on that river.

दिल्ली विद्युत प्रदाय सस्थान को दिया गया ऋण

*1094. **श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को अब तक कुल कितना ऋण दिया है ;

(ख) वित्तीय वर्ष 1971-72 मे उक्त सस्थान को कितना ऋण देने का प्रस्ताव हैं ; और

(ग) उक्त संस्थान को पहले से दिये गये ऋण पर ब्याज किस दर से लिया गया और 1971-72 में दिये जाने वाले प्रस्तावित ऋण पर ब्याज किस दर से लिया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) 1939-40 से अब तक दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई ऋण की कुल रकम रु० 69.14 करोड़ है ।

(ख) आशा है कि 1972-72 के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को ऋण के रूप में रु० 6.95 करोड़ की रकम दी जाएगी । इसमें से 1 करोड़ रुपये का ऋण पहले ही दिया जा चुका है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार पहले दिये जा चुके ऋणों पर लगाये जाने वाले ब्याज की दरों का समय समय पर निर्धारण करती रही और ये दरें प्रति वर्ष शुद्ध 3½ प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच घटती बढ़ती रही । वर्ष 1971-72 के दौरान दिये गये ऋणों के ब्याज की दर प्रतिवर्ष शुद्ध 6 प्रतिशत है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री महोदय ने जो विवरण सभा पटल पर रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि इस साल 6 करोड़ रुपये का ऋण उन्हें दिया जायेगा तो मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि उनकी माग कितनी राशि की थी और जो ऋण मांगा उसमे किन किन मदों पर खर्च करने वाले हैं उसकी कोई सूची दी थी ? यदि हां, तो वह सूची क्या है ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : The Fourth Plan provision for the Delhi city is about Rs. 42 crores. Out of that Rs. 2½ crores have been allotted for the NDMC and the balance of Rs. 39½ crores is for the DESU. From year to year, the money will be given according to the requirements. This year it is about Rs. 6.95 crores. The first instalment is

being released and that is for the purpose of maintaining their transmission systems and the generators.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने यह पूछा था कि कितना उन्होंने मांगा था और कितना आपने दिया है—पहले इस प्रश्न का उत्तर आ जाये तो मैं दूसरा प्रश्न करूं ।

DR. K. L. RAO : As I have submitted, the total amount is fixed for five years and it is about Rs. 42 crores, out of which Rs. 39½ crores is for the DESU. It will be spread over five years. It is likely that in the course of discussions they may have asked for some thing more, but I am not aware of that. The Planning Commission has fixed the amount for this year at Rs. 6 95 crores. That is more or less adequate.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री महोदय ने इस वक्तव्य मे बताया है कि हमने जो पहले लोन दिया था उस पर साढे तीन प्रतिशत से लेकर 6 प्रतिशत तक का ब्याज लिया है और अब 6 प्रतिशत का ब्याज निश्चित किया है तो मै आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हू कि यह जो ब्याज की दर बढ़ाई गई है उसका क्या कारण है और पहले की दरो पर आप लोन क्यो नहीं दे रहे हैं ?

DR. K. L. RAO : The rates of interest vary from time to time. In this particular case, the loans are given at the rate of 8½ per cent interest, and forready payment, a rebate of 2½ percent is allowed and that is how 6 percent comes in. If the DESU does not pay in time, they have got to pay much higher rates of interest.

श्री एच० के० एल० भगत : मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो लोन दिया गया है उसकी वापसी सेन्ट्रल गवर्नमेंट को डेसू शेड्यूल के मुताबिक कर रही है या नही ?

DR. K. L. RAO : As regards the recovery of these loans, these loans are repayable in 15 years. In the first year only the interest is payable and the DESU has been making payments.

Creation of a Zonal or Divisional Headquarters for Southern Railway at Bangalore

*1095. SHRI DHARMARAO AFZALPURKAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether representations have been received by his Ministry regarding the creation of a Zonal or Divisional Headquarters of the Southern Railway in Bangalore keeping in view the industrial importance of the city ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) No representation of creating the Zonal Headquarters of the Southern Railway at Bangalore has been received.

However, suggestions for setting up an additional divisional headquarters of the Southern Railway at Bangalore have been received.

(b) The creation of an additional divisional headquarters at Bangalore, besides the one at Mysore is not considered justifiable.

SHRI K. MALLANNA : Is there any proposal to convert from metre gauge to broad gauge the lines from Bangalore to Miraj and Bangalore to Guntakal and to introduce electrification from Madras to Bangalore, in view of the industrial importance of Bangalore ?

SHRI HANUMANTHAIYA : The question does not arise out of the original question.

SHRI K. MALLANNA : In view of the industrial importance of Bangalore, it becomes relevant.

SHRI HANUMANTHAIYA : Though the two hon. members are trying to help me because that is my constituency, still I have to adhere strictly to the original question. The point he is making does not come within that question.

Expansion of Kerala Ceramics Limited Kundara

*1096. SHRI C. K. CHANDRAPPAN :
SHRIMATI BHARGAVI THANKAPPAN :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the Kerala Government has